

भारत सरकार
पोत परिवहन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3136 जिसका उत्तर
गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है

बकिंघम नहर का जलमार्ग के रूप में विकास

3136. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का विचार काकिनाडा-पुड्डुचेरी के बीच बकिंघम नहर को नदी परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करने और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तक करने का है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;
- (ग) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश यथा काकिनाडा, राजामहेन्द्रकवर्मम, ताडेपतलीगुडेम, इलुरु, विजयवाडा, कोथापट्टनम, मर्ईपडु, दुगाराजापट्टनम में आठ टर्मिनल स्थापित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और
- (घ) क्या हमारे देश में पोत परिवहन के माध्यम से मालवहन के संबंधित क्षमता केवल 0.28 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों जैसे नीदरलैंड की 42 प्रतिशत, फ्रांस की 15 प्रतिशत, हंगरी की 15 प्रतिशत, जर्मनी की 19 प्रतिशत, बेल्जियम की 13 प्रतिशत, यूएसए की अंतर्देशीय जलमार्गों से 15 प्रतिशत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में यूरोपीय संघ से सीखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) जी, नहीं। काकिनाडा-पुड्डुचेरी के बची बकिंघम नहर को नदी परिवहन प्रणाली के रूप में विकसित करने और इसका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) कृष्णा नदी के विजयवाडा-मुक्त्याला जलखंड, जो आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का भाग है, पर नौचालन का विकास करने के लिए 96 करोड़ रु. की लागत पर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस जलखंड के इंटरवेंशनों में दुर्गा घाट, भवानी आईलैंड, अमरावती और वेदाद्री पर फ्लोटिंग टर्मिनल और इब्राहिमपट्टनम, हरिश्चंद्रपुरम, मुक्त्याला तथा मदीपाड़ु पर स्थाई टर्मिनल शामिल हैं।

(घ) वर्तमान में भारत के कुल परिवहन क्षेत्र में अंतर्देशीय जलमार्ग (आईडब्ल्यूटी) की मॉडल हिस्सेदारी लगभग 1.0% है और आईडब्ल्यूटी की मॉडल हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना और तकनीकी रूप से व्यावहारिक नए राष्ट्रीय जलमार्गों पर नौचालन सुविधाओं का विकास।